

दिल्ली अक्षरधाम मंदिर में 108 फीट ऊंची मूर्ति, चर्चा का विषय?

Travelling 108 feet statue was so special: दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में 108 फिट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित की गई है। जो काफी स्पेशल है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जानें इस मूर्ति की...

• जालंधर ब्रीज . फीचर

दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में स्थापित मूर्ति इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों के दिमाग में सवाल है कि आखिर ये मूर्ति है किसकी और इसका साइज भी लोगों को काफी हैरान कर रहा है। 108 फिट ऊंची ये मूर्ति एक पैर पर टिकी है और दोनों हाथों को ऊपर तरफ किया गया है। मूर्ति के इतने सारे एंगल इसे आखिर किस तरह हवा में टिकने में मदद कर रहे, ये सवाल भी लोगों के मन में है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मूर्ति किसकी है और किस साइंस से इसे खड़ा किया गया है।

भगवान स्वामीनारायण की है ये मूर्ति अक्षरधाम मंदिर का पूरा नाम स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है। स्वामीनारायण संत थे जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था और सात साल तक लगातार नंगे पैरों से एक जगह से

दूसरी जगह की धार्मिक यात्रा करते रहे। ये मूर्ति उसी 11 साल के बालयोगी रूप नीलकंठ वर्णी की है। जिन्होंने 1792 में घर छोड़कर नंगे पैर 12 हजार किमी का सफर तय किया। फिर नेपाल के मुक्तिनाथ में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में दोनों हाथों को ऊपर कर एक पैर पर खड़े होकर कई महीनों तक घोर तपस्या की थी। ये मूर्ति उसी तपो मुद्रा के रूप में हैं। इसलिए ये मूर्ति बेहद खास है। अब जानें आखिर इतनी ऊंचाई की मूर्ति के इतने सारे एंगल होने के बाद इसे खड़ा कैसे किया गया है।

108 फिट ऊंची कई किलो वजन की मूर्ति को कैसे खड़ा किया गया है? ये सवाल मन में इसलिए आ रहा क्योंकि जब भी ऊंची मूर्तियां बनाई जाती हैं तो उनके बेस को चौड़ा रखा जाता है। लेकिन इस मूर्ति का सारा भार एक पैर के एंगल पर आ रहा है। जिसे साइंस की लैंग्वेज में बटिकल केंटी लिबर कहते हैं।

इस मूर्ति को पंच धातु से बनाया गया है। जिसमें तांबे का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। वहीं मूर्ति को एक पैर पर टिकाने के लिए अंदर स्ट्रॉंग मेटल से ढांचा बनाया गया है। जो कि जमीन के अंदर कंक्रीट के ढांचे से डायरेक्ट जुड़ा है। जिसकी वजह से ये मूर्ति इतने एंगल पर होने के बाद भी हवा में हिलती नहीं है।

मंदिर का स्ट्रक्चर है इस मूर्ति के लिए खास

100 एकड़ परिसर में फैले इस मंदिर को सबसे पुराने मारु गुर्जर आर्किटेक्चर की मदद से तैयार किया गया है। वास्तुशास्त्र और पंचशास्त्र के नियमों के मुताबिक इस मंदिर को तैयार किया गया है। जिसमें सैंड पत्थर और मार्बल को इस तरह के डिजाइन बनाकर जोड़ा गया है कि वो एक दूसरे में पजल की तरह सेट हो जाते हैं या इंटरलॉक हो जाते हैं। वहीं इस मंदिर की नींव में पत्थरों और रेत की लेयर बिछाकर वायर से बांधा गया है। फिर उसके ऊपर डेढ़ मीटर कंक्रीट बिछाया गया है और फिर उसके ऊपर साढ़े छह मीटर तक पकी हुई ईंटों को बिछाया गया है। इस नींव में पूरे 5 मिलियन ईंटों को लगाया गया है। इतने सॉलिड नींव के ऊपर पूरा मंदिर खड़ा है। जिसमें बीस से भी ज्यादा भारी-भरकम मूर्ति है और साथ ही नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी



मंदिर के प्रांगण में की गई है। तो मूर्ति से पहले इस मंदिर के नींव के बारे में जानना भी जरूरी है। जो बेहद मजबूत है।

LIFE MANTRA

महिलाएं खुद को चुनें, अपने सपनों पर विश्वास करें- सुधा मूर्ति

लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति अपने सरल लेकिन गहरे विचारों के लिए जानी जाती हैं। महिलाओं के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और जीवन में आगे बढ़ने को लेकर उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं।



• जालंधर ब्रीज . फीचर

प्रसिद्ध लेखिका, समाजसेवी और इंफोसिस फाउंडेशन से जुड़ी सुधा मूर्ति अपने जीवन अनुभवों और सादगी भरे विचारों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हमेशा शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में सकारात्मक बदलाव पर जोर दिया है। खासकर महिलाओं के लिए उनके विचार बेहद प्रेरणादायक माने जाते हैं। उनके अनुसार, एक महिला की असली ताकत उसके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता में होती है। आइए जानते हैं महिलाओं के लिए सुधा मूर्ति की कुछ ऐसी सीखें जो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं।

1. खुद को चुनना सीखें

सुधा मूर्ति कहती हैं, 'खुद को बिना अपराधबोध या माफी के चुनें। अपनी शांति की रक्षा करें, क्योंकि वही आपकी असली शक्ति है।' अक्सर महिलाएं परिवार, काम और समाज की जिम्मेदारियों के बीच खुद को पीछे रख देती हैं। लेकिन अपनी खुशी और मानसिक शांति को महत्व देना भी उतना ही जरूरी है। जब आप खुद का ख्याल रखती हैं, तभी दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाती हैं।

2. आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनें

उनका एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश है कि 'एक महिला को हमेशा आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कमाई नहीं भी कर रही हैं, तो भी कुछ बचत जरूर रखें।' आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को आत्मविश्वास देती है और जीवन के फैसले लेने की ताकत भी।

3. खुद पर विश्वास रखें

सुधा मूर्ति का मानना है कि आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। वे कहती हैं, 'आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और भी कैसे करेगा।' जब कोई व्यक्ति अपनी सशक्त बनती हैं।

क्षमताओं पर भरोसा करता है, तो वह मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस रखता है।

4. सपनों के साथ मेहनत भी जरूरी

सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। सुधा मूर्ति कहती हैं, 'सिर्फ दृष्टि (विजन) बिना काम के एक सपना है और काम बिना लक्ष्य के सिर्फ समय बिताना है। लेकिन जब लक्ष्य और काम साथ होते हैं, तो दुनिया बदल सकती है।' इसलिए सपनों को हकीकत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है।

5. सच बोलने का साहस रखें

कई बार सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन अपने विचारों और सच्चाई के साथ खड़े रहना जरूरी है। उनका कहना है, 'अपनी सच्चाई कहें, चाहे आपको आवाज कांप ही क्यों ना रही हो।' यह संदेश महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता है।

6. बदलती सोच की जरूरत

आज की महिलाएं दया या सहानुभूति नहीं चाहतीं, बल्कि बराबरी और सम्मान चाहतीं हैं। सुधा मूर्ति का कहना है, 'आज की महिलाएं सहानुभूति या दया नहीं चाहतीं, वे बदलाव चाहती हैं- खासकर सोच में बदलाव।' समाज में असली बदलाव तब आता है जब लोगों की सोच बदलती है और महिलाओं को बराबरी का अवसर मिलता है।

जीवन मंत्र : सुधा मूर्ति के विचार सिंपल जरूर हैं, लेकिन उनमें जीवन की गहरी समझ छिपी है। उनका संदेश स्पष्ट है- महिलाओं को खुद पर विश्वास करना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब महिलाएं आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन के फैसले लेती हैं, तभी वे सच मायनों में सशक्त बनती हैं।

रोटी-चावल के साथ अच्छी लगती है करेले की सूखी सब्जी, सीखिए बनाने का तरीका

गर्मी के मौसम में करेला खूब आता है। ये सेहत के लिए बेहतरीन होता है, लेकिन इसके कड़वे स्वाद के कारण बच्चे और बड़े दोनों ही इसे खाना कम पसंद करते हैं। यहां बताई सूखी करेला की सब्जी स्वाद में अच्छी लगती है, सीखिए बनाने का...

• जालंधर ब्रीज. रसिपी

करेला एक ऐसी सब्जी है जो दवा की तरह काम करती है। इसका स्वाद भले ही कड़वा हो लेकिन इसे सेहत का खजाना माना जाता है। यह खून में ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करता है। इसी के साथ करेले में कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट को देर तक भरा रखता है।

करेले की कड़वाहट की वजह से बहुत से लोग इसे खाने से कतराते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए, तो यह बेहद टेस्टी लगते हैं। बहुत से घरों में करेला भरवां तरीके से बनाया जाता है। लेकिन इसकी सूखी सब्जी भी स्वाद में जबरदस्त लगती हैं। हम आपके लिए सूखे करेले की सब्जी बनाने की एक बेहतरीन रसिपी लेकर आए हैं। जो रोटी-चावल के साथ अच्छी लगती है।

करेले की सूखी सब्जी

बनाने की सामग्री

आधा किलो करेला, आधा छोटा चम्मच बेसन, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी,एक चम्मच नमक, दो बड़े चम्मच नींबू का रस, दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच गरम मसाला, 7-8 मेथी दाना, एक चम्मच



साबुत धनिया, दो चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, कटा हुआ हरा धनिया।

करेले की सूखी सब्जी

बनाने की विधि

करेले की सूखी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले करेले को पानी से धो लें और फिर गोल-गोल थोड़ी मोटी स्लाइस में काट लें। अब इन्हें एक कटोरे में रखें और ऊपर से नमक डालें। अच्छे से हाथों से मिक्स करें और फिर जब पानी निकलने लगे तो करेले को हाथों में लेकर अच्छे से निचोड़ लें और फिर एक

तरफ रखें। अब अलग रखे करेले में लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन और हल्दी पाउडर डालें। अच्छे से मिक्स करें और फिर इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालकर कुछ देर के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और फिर जीरा, मेथी दाना, हींग, सौंफ, कलौंजी डालकर अच्छे से चटका लें। फिर मसाले के साथ मिक्स किए करेले को तेल में डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। जब करेले अच्छे से पक जाएं तो इसमें नमक और अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालें। अंत में हरा धनिया डालें और सर्व करें।

• जालंधर ब्रीज. हेल्थ केयर

आयुर्वेद में कई सारे फूड कॉम्बिनेशन को खाने से मना किया जाता है। ये फूड कॉम्बिनेशन कई तरह के रोगों के बढ़ने का कारण बनते हैं। ऐसा ही एक फूड है व्हाइट साँस पास्ता, जिसे बनाने में यूज होने वाले इग्रीडिएंट्स में ऐसे फूड्स को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो आपके हेल्थ के लिए रेड फ्लैग हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि आयुर्वेद की डॉक्टर बता रहीं। विटिलिगो यानी सफेद दाग एक्सपर्ट डॉक्टर निकिता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लोगों को सावधान किया है कि अगर आपका फेवरेट फूड व्हाइट साँस पास्ता है तो आप इस बीमारी के निशाने पर हो सकते हैं।

व्हाइट साँस पास्ता से हो सकती है ये बीमारी : डॉक्टर का कहना है कि व्हाइट साँस पास्ता मैदा, नमक, बटर और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। जिसमे दूध और नमक आयुर्वेद के मुताबिक बिल्कुल गलत फूड कॉम्बिनेशन है। इसे मिलाकर बना पास्ता विटिलिगो की समस्या बढ़ा सकता है। डॉक्टर के मुताबिक किसी भी स्किन डिसऑर्डर में जब वो इन फूड्स को देखते हैं तो निदान के तौर पर देखते हैं कि ये फूड्स कॉम्बिनेशन ट्रिगर का काम कर रहे हैं।

कब व्हाइट साँस पास्ता खाना हो सकता है खतरनाक : डॉक्टर ने बताया कि अगर आप कभी एकाध बार व्हाइट साँस पास्ता खा लेते हैं तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली इसे खाते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो व्हाइट साँस पास्ता खाते हैं या घर पर ऑर्डर करके खाते हैं या घर में भी बनाकर खाते हैं और लगातार अक्सर ही खाते हैं तो आप सबसे ज्यादा विटिलिगो जैसी बीमारी के निशाने पर हैं। यहीं नहीं दूध नमक जैसे गलत फूड कॉम्बिनेशन को खाकर हुए विटिलिगो के तेजी से शरीर के ज्यादा हिस्से में फैलने का भी खतरा रहता है।

तो अगली बार जब भी आप व्हाइट साँस पास्ता को खाएं तो डॉक्टर के बताई इन बातों को जरूर याद कर लें। **क्या है विटिलिगो :** विटिलिगो एक स्किन रोग है जिसमे स्किन के कुछ दूर के हिस्से का रंग उड़ जाता है। जिससे स्किन का रंग नेचुरल कलर के गाढ़ा या हल्का दिखने लगता है। आमतौर पर ये हल्का हो जाता है जिसे सामान्य भाषा में लोग सफेद दाग भी बोलते हैं। स्किन के

व्हाइट साँस पास्ता है फेवरेट फूड तो हो सकती है ये बीमारी, आयुर्वेद की डॉक्टर ने किया सावधान

Health



जिस हिस्से का रंग उड़ जाता है वहां पर उगे बालों का रंग भी हल्का हो जाता है और वो सफेद या सिल्वर कलर के दिखने लगते हैं। विटिलिगो होने का कारण स्किन के सेल्स से मेलानिन प्रोडक्शन बंद होने की वजह से होता है।

मेलानिन ही स्किन को रंग या पिगमेंटेशन देने का काम करता है।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

वीडियो कॉल से जुड़े सवालों को डॉक्टर से पूछते हैं लोग, जानिए जवाब

नन्हें बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। बच्चों की नटखट हरकतों को देखने के लिए अक्सर लोग बेबी से मिलने आते हैं और जो लोग नहीं आ पाते हैं वह बच्चों को वीडियो कॉल के जरिए देखते हैं। पर क्या बच्चे को वीडियो कॉल पर बात करवानी...

जालंधर ब्रीज (फीचर) . बच्चा जैसे ही कोई नई हरकत करता है तो पेरेंट्स तुरंत फोन उठाकर उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। या फिर उन लोगों को तुरंत वीडियो कॉल लगाते हैं। हालांकि, अक्सर पेरेंट्स के मन में सवाल आते हैं कि क्या ऐसा करना सेफ है या नहीं। तो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है जिसमें वह वीडियो कॉल से जुड़े उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं।



1) क्या हम बच्चे को वीडियो कॉल पर बात करवा सकते हैं? पेरेंट्स अपने बच्चे को फोन से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए अक्सर बच्चे के सामने खुद भी फोन चलाने से बचते हैं। लेकिन कई बार दूर रह रहे लोगों से बात करवाने के लिए वह वीडियो कॉल पर बात करवा देते हैं। लेकिन मन में सवाल रहता है कि क्या बच्चे को वीडियो कॉल पर बात करवाएं या नहीं। ऐसे में डॉक्टर का मानना है कि हां आप बच्चे को वीडियो कॉल पर बात करवा सकते हैं?

2) बच्चे को किस उम्र से वीडियो कॉल पर बात करवा सकते हैं?

डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने के बच्चे को आप वीडियो कॉल पर बात करवा सकते हैं। क्योंकि इस समय पर बच्चा बात करने के लिए तैयार होता है और अगर पीकाबू करने पर बेबी प्रतिक्रिया देता है तो वह वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार है।

3) क्या बच्चे को इसकी आदत हो जाएगी या कुछ नुकसान होगा?

ऐसे में डॉक्टर ने कुछ टिप्स शेयर की हैं जिन्हें अपनाकर न बच्चे को कुछ नुकसान होगा और न आदत लगेगी। वीडियो कॉल की टाइमिंग कम समय की रखें। 2 से सिर्फ 5 मिनट की। इसके अलावा फोन को बच्चे से एक फीट दूर रखें। इसके अलावा रूम की लाइट को भी ऑन रखना है। डार्क लाइट में बच्चे को वीडियो कॉल पर बात नहीं करवानी है। एक बात जो आपको जरूर ध्यान रखनी है वह ये है कि सोने से पहले बच्चे को वीडियो कॉल पर बात न करवाएं।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

विधायी नेतृत्व: नीति निर्धारण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की परिवर्तनकारी शक्ति

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भारत के समक्ष एक असाधारण अवसर है— अपनी विधायिकाओं को नया आकार देने, महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने और एक ऐसे लोकतंत्र की रचना करने का— जो सही मायनों में अपने लोगों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता हो। जब महिलाएँ शासन में अपना उचित स्थान ग्रहण करती हैं, तब सभी की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर नीतियाँ बनती हैं, और राष्ट्र अधिक उद्देश्य और शक्ति के साथ आगे बढ़ता है।

सितंबर 2023 में पारित संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम — नारी शक्ति वंदन अधिनियम — हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधारों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाया गया यह कानून हमारे देश के लोकतांत्रिक ढाँचे में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन में निहित यह ऐतिहासिक कानून, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हुए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक साहसिक कदम है।

यह मात्र संवैधानिक प्रावधान से कहीं बढ़कर है—यह एक परिवर्तनकारी विजन का संस्थागत रूप है, जहाँ महिलाएँ केवल लोकतंत्र में भागीदारी ही नहीं करतीं, बल्कि उसके ताने-बाने को भी आकार देती हैं।

भारतीय शासन व्यवस्था की पटकथा फिर से लिख रहा है मिशन कर्मयोगी

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

कल्पना करें कि राजस्थान के दूरदराज के किसी कोने में जिला कलेक्टर को एक ऐसी महत्वाकांक्षी कल्याण योजना की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसके बारे में उसकी जानकारी बहुत कम है। एक दशक पहले उसे जानकारी के लिए कहीं धूल खा रही किसी नियमावली का सहारा नाना होता। या फिर वह अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी को तीन बैठकों और लंच के बाद खाली होने का इंतजार करता। उसकी उम्मीद उस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी टिकी हो सकती थी जो शायद एक या दो साल में कभी आता। लेकिन आज वह अपने फोन के जरिए आईगांट (ईटिग्रेटेड गर्वनमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म) पर लॉग ऑन करता है। उसे मिनटों में ही अपनी जरूरत के अनुरूप एक सुव्यवस्थित कार्यकुशलता आधारित पाठ्यक्रम मिल जाता है। वह शाम तक सूचनाओं और आत्मविश्वास से लैस होकर योजना के लाभार्थियों की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहा होता है। यह बदलाव देखने में छोटा लग सकता है मगर हकीकत में किसी क्रांति से कम नहीं है।

चमक-दमक से दूर धैर्य के साथ पांच साल पहले शुरू किया गया मिशन कर्मयोगी एक क्रांति ला रहा है। यह नए भारत के लिए एक नई तरह के प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने के उद्देश्य से चुपचाप काम कर रहा है।

इसके महत्व को समझने के लिए हमें पहले संदर्भ को जानना होगा। 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री के निर्धारित लक्ष्य तक यूं ही नहीं पहुंचा जा सकता।

माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास को दिए गए निरंतर समर्थन ने लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों को हकीकत में बदलने की मजबूत प्रेरणा प्रदान की है।

भारत की लोकातांत्रिक संस्थाओं को केवल अधिक महिलाओं की ही नहीं, बल्कि ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जिनके पास नीतिगत परिणामों को आकार देने के लिए अधिकार, क्षमता और पर्याप्त अवसर हों। वर्तमान सरकार ने पिछले एक दशक में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिससे इस विधायी परिवर्तन के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। जन धन खाताधारकों में 56% से अधिक महिलाएँ हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलता है। मुद्रा योजना के लगभग 67% लाभार्थी

महिलाएँ हैं, जो उद्यमिता में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 73% से अधिक मकान महिलाओं के नाम पर हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शनों ने घरेलू जीवन स्तर में सुधार किया है। ये सभी कदम एक स्पष्ट नीतिगत दिशा — भागीदारी के जरिए सशक्तिकरण— की ओर इंगित करते हैं हालांकि, अब ध्यान भागीदारी से आगे बढ़कर निर्णय-लेने तक पहुँचने पर केंद्रित है।

हमारे देश का अपना अनुभव एक मजबूत मानक प्रस्तुत करता है। स्थानीय स्तर पर, अब पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों में से लगभग 50% महिलाएँ हैं,

यानी 12 लाख से अधिक नेताओं के रूप में वे स्थानीय शासन को दिशा दे रही हैं। उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महिला-नेतृत्व वाली स्थानीय संस्थाओं ने विकास से जुड़े जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य देखरेख जैसे प्रमुख मुद्दों पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है, जो दर्शाता है कि नेतृत्व में विविधता नीति निर्माण में सकारात्मक बदलाव लाती है।

अब यह प्रश्न नहीं रह गया है कि महिलाएँ प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं या नहीं; इसके प्रमाण पहले से मौजूद हैं। अब समय आ गया है कि भारत की उच्च विधायी संस्थाएँ महिलाओं के नेतृत्व को पूर्ण रूप से अपनाएँ और उसे बढ़ाएँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने पहले ही आधार तैयार कर दिया है, जो सार्थक प्रतिनिधित्व के लिए एक मजबूत संरचनात्मक नींव प्रदान करता है। राजनीतिक दलों के पास अब इस गति को आगे बढ़ाने-उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित करने, चुनावी अभियान के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुँच का विस्तार करने तथा महिला नेताओं के लिए स्पष्ट और सशक्त मार्ग तैयार करने का जबरदस्ता अवसर है। उचित सुधारों के साथ, राजनीतिक दल विधायी समावेशन को विजन से जीवंत और जीती-जागती हकीकत में परिवर्तित कर सकते हैं।

सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में संस्थागत तत्परता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बार निर्वाचित होने वाले विधायकों को सशक्त नीतिगत अनुसंधान, समग्र विधायी प्रशिक्षण और मजबूत सहकर्मी नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करके, सरकार उन आधारों में निवेश कर रही है जो बड़ी हुई भागीदारी को अधिक प्रभावी और सटीक निर्णय-लेने में परिवर्तित करते हैं।

संस्कृति को, समय-समय पर होने वाली और केवल नियमों के पालन तक सीमित प्रक्रिया से बदलकर, एक निरंतर चलने वाली, भूमिका-आधारित और स्वयं-निर्देशित विकास यात्रा में रूपांतरित करना इसका मकसद है। जैसा कि आयोग इसका वर्णन करता है, यह बदलाव 'कर्मचारी'—यानी नियमों का पालन करने वाले एक पदाधिकारी से 'कर्मयोगी' बनने की ओर है: एक ऐसा लोक सेवक जो किसी उद्देश्य, सेवा-भाव और उत्कृष्टता से प्रेरित हो।

पाँच वर्षों के बाद, ये आंकड़े अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। ‘आईगांट’ (इंटीग्रेटेड गर्वनमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) प्लेटफॉर्म पर अब 1.5 करोड़ से अधिक सरकारी अधिकारी सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में जुड़े हैं — यह एक ऐसी संख्या है जो शुरूआत के समय काल्पनिक लगती थी। 4,600 से अधिक योग्यता-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से, इन अधिकारियों ने 8.3 करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। अधिक पिछले 'राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह' के दौरान, भागीदारी के परिणामस्वरूप 4.5 मिलियन घंटे के पाठ्यक्रम नामांकन और 3.8 मिलियन घंटे की वास्तविक शिक्षा दर्ज की गई। ये केवल अमूर्त आंकड़े नहीं हैं। दर्ज किया गया प्रत्येक घंटा भारत में कहीं न कहीं एक लोक सेवक का प्रतिनिधित्व करता है — छत्तीसगढ़ में एक राजस्व निरीक्षक, पुणे में एक शहरी स्थानीय निकाय अधिकारी, मणिपुर में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये सब अपने साथी नागरिकों को बेहतर सेवा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं।

जो बात आईगांट प्लेटफॉर्म को वास्तव में परिवर्तनकारी बनाती है, वह केवल इसका पैमाना नहीं है, बल्कि इसकी 'पहुँच की संरचना' है।

शुरुआती कदमों से भविष्य के सपनों तक : हर बच्चे के लिए सीखने का नया स्वरूप

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

हर साल, जब स्कूलों के द्वार नए शैक्षणिक सत्र के लिए खुलते हैं, तो भारत सामूहिक संकल्प के सबसे गहन उद्घारणों में से एक का साक्षी बनता है। पहाड़ों और तटों से लेकर शहरों और दूरदराज के गांवों तक, लाखों बच्चे कभी-कभी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद, नए जोश, नई आकांक्षाओं और अपार संभावनाओं के साथ अपनी कक्षाओं में कदम रखते हैं। यह एक शांत लेकिन शक्तिशाली राष्ट्रीय क्षण है। इस वर्ष भी लाखों करोड़ बच्चों ने पहली कक्षा में प्रवेश लिया है, जो आशा और एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी दोनों को समेटे हुए है।

भारत का स्कूली ढांचा बेहद विशाल है। इसमें 14.7 लाख से अधिक स्कूल, लगभग 25 करोड़ नामांकित छात्र और एक करोड़ से ज्यादा शिक्षक शामिल हैं। ये संख्याएँ केवल प्रशासनिक स्तर को मापने का जरिया भर नहीं हैं, बल्कि ये शिक्षा के माध्यम से हमारे देश के भविष्य को गढ़ने की एक मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने रटने की आदत से आगे बढ़कर जिज्ञासा, समझ और समग्र विकास (होलिस्टिक डेवलपमेंट) को सीखने के केंद्र में रखा है। हर नया शैक्षणिक सत्र उस सपने को साकार करने की दिशा में एक

सार्थक कदम है।

बालवाटिका लागू होने से अब छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई स्कूल व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। इससे बच्चे पहली कक्षा में बेहतर तैयारी और मजबूत बुनियादी कौशल के साथ प्रवेश करते हैं। बच्चे का स्कूल में दाखिला उसके जीवनभर के सीखने और समाज से जुड़ने की शुरुआत होता है। इसलिए जरूरी है कि यह सफर खुशी, अच्छे माहौल और अपनापन महसूस कराने वाला हो।

सीखने का सफर: पहले कदम से आत्मविश्वास तक स्कूल का पहला दिन खास होता है। इसमें थोड़ी झिझक होती है, तो नए शुरुआत की खुशी भी होती है। छोटे-छोटे बच्चे अपने बड़े-बड़े भाव लेकर स्कूल आते हैं और उनकी जिज्ञासु आंखें एक नई दुनिया देखती हैं। जब बच्चे खुद को सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, तो वे खुलने लगते हैं। वे ज्यादा भाग लेते हैं, सवाल पूछते हैं और उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता जाता है। शुरुआती साल खेल, खोज और नई चीज़ें सीखने पर आधारित होने चाहिए, यही जीवनभर की सीखने की यात्रा का शुरुआत है।

अच्छे रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। एक समझदार और देखभाल करने वाला शिक्षक बच्चे की जिदगी बदल सकता है। सहयोगी

कक्षा माहौल बच्चे की चुप्पी को भागीदारी में और भागीदारी को आत्मविश्वास में बदल सकता है। जब बच्चा खुद को सच में समझा और सुना हुआ महसूस करता है, तो उसकी जिज्ञासा हिम्मत में बदल जाती है। और जब उसे अपनापन महसूस होता है, तो वह अपनी आवाज़ पहचानने लगता है।

इन प्रारंभिक वर्षों के केंद्र में बुनियादी साक्षरता और अंकगणित के प्रति एक मजबूत राष्ट्रीय प्रतिबद्धता निहित है। निरुण भारत मिशन के माध्यम से, भारत ने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है: कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चा समझ के साथ पढ़ सके और बुनियादी अंकगणित कर सके। ध्यान उत्तरों को रटने से हटकर अवधारणाओं को समझने पर केंद्रित है। कक्षाओं को बच्चों को केवल उत्तर दोहराने के बजाय प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण अकादमिक शिक्षा से परे है। कला, खेल और मूल्य सीखने की प्रक्रिया के अनिवार्य अंग हैं। शिक्षा को 'संपूर्ण बच्चे' का निर्माण करना चाहिए— न केवल मन का, बल्कि शरीर और हृदय का भी। शारीरिक गतिविधि और पोषण दैनिक स्कूली जीवन का अभिन्न अंग हैं। एक स्वस्थ बच्चा



डॉ. अरविंद सिंह (केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं)

बेहतर सीखता है, अधिक भाग लेता है और आत्म-सम्मान की स्वस्थ भावना के साथ विकसित होता है।

उभरती चुनौतियों का सामना

वैश्विक स्तर पर, बच्चों की जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। खान-पान की आदतों में बदलाव और शारीरिक गतिविधि में कमी कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है। भारत इस चुनौती का सक्रिय रूप से सामना कर रहा है। अनिवार्य शारीरिक शिक्षा, स्कूलों में मोटापे से निपटने के लिए 'ऑयल बोर्ड' और 'शुगर बोर्ड' जैसे उपाय और पोषण गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने वाली मजबूत पीएम-पोषण योजना स्कूलों को स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली की ओर उन्मुख कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो स्वास्थ्य को समग्र विकास का केंद्र मानती हो।

हालाँकि प्रौद्योगिकी शिक्षा और पहुँच के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है, सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से स्क्रीन टाइम, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। यह एक वैश्विक चिंता है, न कि केवल भारत तक सीमित। स्कूलों और परिवारों को यह सुनिश्चित

अडिग प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इस ऐतिहासिक सुधार की वास्तविक क्षमता केवल इसके प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। अधिनियम की प्रावधानों को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की आवाज़ को सिर्फ मान्यता ही न मिले, बल्कि देश की लोकातांत्रिक संरचना में इसे संस्थागत रूप से समाहित किया जा सके। इसके जल्द लागू होने से न केवल समावेशी शासन को गति मिलेगी, बल्कि यह बेहतर प्रतिनिधित्व और न्यायसंगत

राजनैतिक परिदृश्य के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा।

दशकों तक, लैंगिक पक्षपात ने भारत के जनसांख्यिकीय और सामाजिक संकेतकों को प्रभावित किया। आज, वह कहानी धीरे-धीरे फिर से लिखी जा रही है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी पहलों ने गहरी जड़ें जमा चुकीं मानसिकताओं की चुनौती देने और लड़की

के मूल्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस-5) में दिखाई देता है, जिसमें 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का लैंगिक अनुपात दर्ज किया गया है, जो सिर्फ संख्यात्मक सुधार ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी संकेत देता है। 'मिशन इंद्रधनुष' जैसे कार्यक्रम जीवन के प्रारंभिक चरण में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करते हैं। 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी', 'पोषण 2.0', तथा 'पोषण अभियान' के प्रयास कुपोषण का समाधान करते हैं—यह मानते हुए कि स्वस्थ बचपन, सशक्त वयस्कता की ओर पहला कदम होता है।

तेजवीर सिंह ने डीसीपीसी सचिव पद संभाला

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

तेजवीर सिंह, आईएसएस (पंजाब कैडर: 1994) ने आज रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी), के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण करने पर सिंह का स्वागत विभाग की निवर्तमान सचिव, निवेदिता शुक्ला वर्मा तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में नियुक्ति से पूर्व, तेजवीर सिंह पंजाब सरकार में तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अपर मुख्य

देहरादून में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य व सड़क सुरक्षा पर मंथन

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देहरादून के संजय आँधोंपीडिक, स्पाइन और मेटरिनिटी सेंटर में स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और जन-जागरूकता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेश बंसल, सांसद, पद्मश्री कन्हैया लाल पोखरियाल, साहित्यकार, डॉ. एस. एन. सिंह, आँधोंपीडिक सर्जन, पद्मश्री डॉ. बी. के. एस. संजय, प्रसिद्ध आँधोंपीडिक सर्जन, और डॉ. गौरव संजय, आँधोंपीडिक सर्जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष एम्स गुवाहाटी के पद्मश्री डॉ. बी. के. एस. संजय ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जाए, इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए



सचिव के रूप में कार्यरत थे।

सिंह, पंजाब कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं

देहरादून में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य व सड़क सुरक्षा पर मंथन



और एम्स संस्थानों को “रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर” के रूप में विकसित किया जाए। मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड सरकार की दो नई नीतियों की घोषणा की: विशेषज्ञ डॉक्टर पहाड़ी क्षेत्रों में छह महीने के रोटेशन पर सेवाएँ देंगे और उनके परिवार के लिए देहरादून और हल्द्वानी में आवासीय सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

विशिष्ट अतिथि नरेश बंसल ने कहा कि नियमों का पालन न होने के कारण दुर्घटनाएँ जारी हैं और कहा, “केवल स्वस्थ पीढ़ी ही विकसित भारत का सपना साकार कर सकती है।” पद्मश्री कन्हैया लाल पोखरियाल ने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया।

माताओं के लिए, संस्थागत समर्थन में काफी विस्तार हुआ है। पीएमएमवीवाई के तहत, 4.28 करोड़ से अधिक महिलाओं को 20,149 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गयी है, जो गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महिलाएँ केवल भाग ही नहीं ले रही हैं—वे नेतृत्व भी कर रही हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में संस्थापक और निर्णायकताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका में लगातार वृद्धि हो रही है और वे नवाचार और उद्यम में भी योगदान दे रही हैं। इस परिवर्तन में वित्तीय समावेशन ने अहम भूमिका निभाई है। पीएमएमवाई के तहत, 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 57.79 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं, जिनमें लगभग 66% लाभार्थी महिलाएँ हैं, प्रत्येक ऋण केवल वित्तीय सहायता का ही नहीं, बल्कि महिलाओं की आकांक्षाओं में विश्वास का भी प्रतीक है। इसके पूरक रूप में, जन धन योजना के तहत वित्तीय समावेश और गहरा हुआ है, जिसके अंतर्गत 57.93 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से 32.29 करोड़ (55.7%) महिलाओं के हैं।

जमीनी स्तर पर, परिवर्तन का पैमाना और भी अधिक प्रभावशाली है। लगभग 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से अधिक स्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिससे सामूहिक सहनशीलता, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मविश्वास का बढ़ावा मिला है। इस इकोसिस्टम ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है और स्वयं सहायता समूहों को 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 84 लाख ग्रामीण महिलाएँ उद्यमी बन चुकी हैं, जबकि 5 करोड़ महिला किसानों ने उन्नत और सतत कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं।

और उनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव रहा है। उन्होंने पंजाब सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा मुख्यमंत्री के सचिव के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया है।

वहीं, निवेदिता शुक्ला वर्मा, आईएसएस को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी।

डॉ. एस. एन. सिंह ने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। डॉ. गौरव संजय ने ‘वन हेल्थ’ अवधारणा समझाते हुए मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य के आपसी संबंध और स्वच्छ वायु, सुरक्षित जल, पीप्टिक भोजन और संतुलित आहार के महत्व पर बल दिया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री कल्याण सिंहरावत ने कहा कि सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का संचालन और समन्वय योगेश अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और सुरक्षित, स्वस्थ और जागरूक समाज बनाने के संकल्प के साथ हुआ।

अपनी पहचान से जुड़ा हो। मैं अपने शिक्षकों से आह्वान करता हूँ कि वे प्रत्येक बच्चे की गति, व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए और अपनी देखरेख में प्रत्येक छात्र के भवनात्मक और मानसिक कल्याण के प्रति सचेत रहते हुए योग्यता-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दें।

माता-पिता की भूमिका शिक्षा विद्यालय के द्वार पर शुरू या समाप्त नहीं होती। घर ही पहला कक्षास्थल है और माता-पिता ही पहले शिक्षक। घर पर बच्चे को अनुभव प्राप्त करते हैं, वही उनके विद्यालय में सीखने के तरीके को आकार देता है। पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और बच्चे के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देना, ज्ञान की जिज्ञासा को पोषित करने के सूक्ष्म कार्य हैं। मैं माता-पिता से आग्रह करता हूँ कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चों को संतुलित पोषण और पर्याप्त नींद मिले, उन्हें प्रतिदिन पर्याप्त शारीरिक गतिविधि और बाहरी वातावरण का अनुभव मिले। माता-पिता को विद्यालय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए और बच्चे की सफलता को केवल अंकों के आधार पर ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, दयालुता और सीखने में निरंतर रुचि के आधार पर भी मापना चाहिए। माता-पिता अपने बच्चे को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं, वह है यह विश्वास दिलाना कि सीखना वास्तव में आनंददायक है।

गुरदासपुर में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति गिरफ्तार; 5 हैंड ग्रेनेड व आईईडी सामग्री बरामद

दो विशेष डेटोनेटर, कोडर और डिकोडर युक्त पीटीटी टाइमर, 9 वोल्ट बैटरी, केबल सहित 1 बाओफेंग वॉकी-टॉकी और ट्रिगर मैकेनिज्म भी बरामद, डीजीपी गौरव यादव ने कहा- यह बरामदगी राज्य में शांति भंग करने के उद्देश्य से उच्च-प्रभाव वाले हमलों की तैयारियों को दर्शाती है

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़/गुरदासपुर

अमृतसर ग्रामीण, गुरदासपुर और काउंटर इंटेलिजेंस विंग के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में आईएसआई समर्थित बम्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान आकाश मसीह और जबलौन के रूप में हुई है, जो दोनों जिला गुरदासपुर के थाना घुमान कलां के गांव दुल्ला नंगल के निवासी हैं। दोनों आरोपियों का

गैंगस्ट्रों पे वार का 79वां दिन : पंजाब पुलिस द्वारा 567 स्थानों पर छापेमारी; 252 गिरफ्तार

पुलिस टीमों ने 80 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की, 72 को पूछताछ के बाद रिहा किया

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

“गैंगस्ट्रों ते वार” मुहिम के 79वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्ट्रों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 567 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि “गैंगस्ट्रों ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमों राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं। 79वें दिन पुलिस टीमों ने एक हथियार बरामद करने के बाद 252 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 19,894 हो गई है।

एसपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जसवीर सिंह गढ़ी ने गृह सचिव और डीजीपी को लिखा पत्र

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने राज्य के गृह सचिव, पंजाब और डीजीपी को पत्र लिखकर पुलिस के एक एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा आयोग के आदेशों की अवहेलना किए जाने के मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि धर्म चंद पुत्र कर्ता राम, निवासी गांव झुंगियां, तहसील बालाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर की शिकायत संख्या क(ग) 113/25 प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में जातिसूचक अपशब्द कहने, मारपीट करने, अपमानित करने, घर पर हमला करने, तेजधार हथियार से वार करने तथा झूठा मामला दर्ज कर उसे रद्द करवाने संबंधी न्याय की मांग की गई थी। प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा पंजाब राज्य



आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ महत्वपूर्ण बरामदगियां हुई हैं, जिनमें पांच हैंड ग्रेनेड, दो विशेष डेटोनेटर, कोडर और डिकोडर युक्त पुश-टू-टॉक (पीटीटी) टाइमर, 9 वोल्ट बैटरी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस

(आईईडी) सामग्री (1 किलोग्राम उच्च विस्फोटक), केबल तथा ट्रिगर सहित एक बाओफेंग वॉकी-टॉकी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि यह मॉड्यूल राज्य में शांति भंग करने के लिए उच्च-प्रभाव वाले आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल विदेशी हैंडलरों द्वारा संचालित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इसके आगे-पीछे के संबंध, व्यापक साजिश और स्थानीय सहयोगी नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) गुरदासपुर आदित्य ने ऑपरेशन का विवरण देते हुए बताया कि टी-प्वाइंट जोगोवाल बेदिया

पेंशनर सेवा पोर्टल को लेकर बैंकों के साथ अहम समीक्षा बैठक भविष्य में पेंशन का भुगतान बैंकों के प्रदर्शन और प्रगति पर सख्ती से निर्भर करेगा: हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री द्वारा सॉफ्टवेयर एकीकरण और जेपीप. के तत्काल अनुपालन के लिए ठोस निर्देश जारी

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को यहां पेंशनर सेवा पोर्टल से संबंधित देरी और महत्वपूर्ण लंबित मुद्दों की समीक्षा के लिए बैंकों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समयसीमा में हुई देरी, अधूरे कार्यों और सिस्टम की कमियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने तत्काल अनुपालन, तेजी से एकीकरण और लंबित मामलों के निपटारे के लिए सख्त निर्देश जारी किए और स्पष्ट किया कि भविष्य में पेंशन भुगतान पूरी तरह बैंकों के प्रदर्शन और वास्तविक प्रगति से जुड़ा होगा। स्थिति की विस्तृत जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने सरकार के रुख, पूर्व में की गई कार्यवाही और सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों से भविष्य की अपेक्षाओं को विस्तार से बताया। बैंकों को संबोधित करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “24 दिसंबर 2025 को हुई हमारी प्रारंभिक बैठक के बाद से मैं इस पूरे मामले पर लगातार नजर रख रहा हूँ, जिसमें बैंकों ने पोर्टल से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न समयसीमाओं का आश्वासन दिया था। 2 फरवरी 2026 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि बैंकों ने निर्धारित समयसीमाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया। इसके बाद बैंकों



के अनुरोध पर समयसीमाओं को सख्ती से संशोधित और बढ़ाया गया।”

इसके बाद की बैठक में अपना दखल का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, “26 फरवरी 2026 की समीक्षा बैठक में नवंबर 2025 की पेंशन के दावों का भुगतान बैंकों को जारी करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह इस शर्त पर था कि बैंक शेष पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र पूरे करें और 31 मार्च 2026 तक लंबित पीपीओ पीडीएफ जमा करें। आगामी महीनों के भुगतान को बैंकों की वास्तविक प्रगति से जोड़ा गया है।” उन्होंने बताया, “नवंबर 2025 के सभी ई-स्कॉल बैंकों द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा भुगतान सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) जमा करने और पेंशनर सेवा पोर्टल को बैंक सॉफ्टवेयर

से जोड़ने (इंटीग्रेशन) की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और केनरा बैंक द्वारा यह एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।”

वित्त मंत्री ने कहा, “बैंकों को मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और पेंशनर सेवा पोर्टल में निर्धारित गणनाओं व फार्मूलों के अनुसार पूरी तरह सही स्कॉल अपलोड करने चाहिए, ताकि उन्हें शीघ्र स्वीकृति मिल सके।” उन्होंने आगे कहा, “बैंकों को लंबित पीपीओ पीडीएफ उपलब्ध कराने और अस्थायी पेंशनरों को बिना किसी देरी के स्वीकृति देने को प्रार्थमिकता देनी चाहिए। जिला कोषागार अधिकारियों द्वारा स्कॉल में उठाई गई त्रुटियों को भी सक्रिय रूप से दूर किया जाए। हमारे पोर्टल के साथ बैंक सॉफ्टवेयर का एकीकरण जल्द से जल्द पूरा करना अनिवार्य है।”

सरकार ने नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस में 50 प्रतिशत छूट की अवधि 15 जून तक बढ़ाई : गुरविंदर सिंह पाबला

चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट ने इसे लाभार्थियों के लिए राहत बताया

• जालंधर ब्रीज. होशियारपुर

चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट, होशियारपुर गुरविंदर सिंह पाबला ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने नॉन-कंस्ट्रक्शन



संबंधी वन टाइम रिलेक्सेशन पॉलिसी की अवधि को बढ़ाकर अब 15 जून 2026 तक कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के बढ़ने से अलॉटी-ट्रांसफरी अब अपनी खाली

पड़ी रिहायशी एवं व्यावसायिक संपत्तियों पर नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस में 50 प्रतिशत छूट का लाभ लेने हेतु आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे। इस फैसले से लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे बची हुई राशि का उपयोग अपने प्लॉट्स पर निर्माण कार्य के लिए कर सकेंगे।

चेयरमैन गुरविंदर सिंह पाबला ने इस फैसले के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान एवं स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री संजीव अरोड़ा की दूरदर्शी सोच और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का सराहनीय उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत लाभ लेने के इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट कार्यालय की ईमेल आईडी thoshiajpur35@gmail.com या फोन नंबर 01882-220980 पर संपर्क कर सकते हैं।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पराली जलाने में कमी लाने की पहल के लिए स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड 2025

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को उसके प्रोजेक्ट “संकट से सफलता तक – पंजाब की स्वच्छ हवा परिवर्तन यात्रा” के लिए पर्यावरण श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित 107वें स्कॉच समिट ‘गवर्नैस ट्रांसफॉर्म’ के दौरान प्रदान किया गया। पिछले पांच वर्षों में पंजाब ने पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए बहु-विभागीय प्रयासों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें रियल-टाइम मॉनिटरिंग और सख्त अनुपालन के साथ-साथ दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय शामिल हैं, जैसे कि सीआरएम मशीनरी की बड़े पैमाने पर तैनाती, कस्टम हायरिंग सेंटरों को मजबूत करना, तथा धान की पराली के बाहरी उपयोग में वृद्धि—जो 8.8 लाख टन से बढ़कर 40 लाख टन वार्षिक हो गया है।

पीपीसीबी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा, “हम इस राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह पंजाब सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत एक जटिल पर्यावरणीय चुनौती का समाधान



किया जा रहा है।” पंजाब राज्य भविष्य में इस दिशा में और बेहतर उपलब्धियां हासिल करने तथा पराली जलाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। स्कॉच अवॉर्ड एक जटिल मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रस्तुतियां, विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन और सार्वजनिक मतदान शामिल होते हैं।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 245 करोड़ रुपये जारी, 2.45 लाख छात्रों को बड़ी राहत

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से गरीब परिवारों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को मिला मजबूत सहारा, सीएम मान के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत पंजाब सरकार के हिस्से के रूप में 245 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के तहत 2 लाख 45 हजार से अधिक पात्र विद्यार्थियों का डेटा प्राप्त हुआ है, जिन्हें इस राशि का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है



और इससे हजारों परिवारों पर पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम हुआ है।

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना हजारों विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है, जिससे वे अपने भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि जब गरीब परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ते हैं, तो इससे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

लोक निर्माण मंत्री ने बरसाती मौसम से पहले सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में निर्मित की जा रही सड़कों की प्रगति के संबंध में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. की अध्यक्षता में आज पंजाब भवन में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बरसात के मौसम से पहले सड़क निर्माण से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में नई तकनीक फुल डेथ रिक्लेमेशन का उपयोग करते हुए ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में 410 किलोमीटर सड़कों को इस तकनीक के माध्यम से पुनर्निर्मित किया जाएगा। इस तकनीक के



जरिए सड़क में पहले से मौजूद रोड मेटल का पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे अतिरिक्त खनन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और सड़कों का स्तर अनावश्यक रूप से ऊंचा होने से भी बचाया जा सकेगा।

कैबिनेट मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश के कारण कार्य में आई देरी को दूर करने के लिए तेजी से काम किया जाए और प्रगति को बढ़ाया जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में हॉट मिक्स प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते प्रतिदिन 200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 30 जून 2026 तक लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

पंजाब सरकार द्वारा उपस्थिति संबंधी सुधारों के साथ मिशन समर्थ 2026-27 की शुरुआत

• जालंधर ब्रीज. चंडीगढ़

पंजाब की शिक्षा क्रांति को अगले चरण में ले जाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा ‘आप’ पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने आज मिशन समर्थ 4.0 की शुरुआत की। यह शिक्षा में वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता लाने वाला प्रमुख बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह नई पहल राज्यव्यापी उपस्थिति ट्रेकिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान करती है, जिसके तहत अभिभावकों को अपने बच्चे की उपस्थिति के बारे में रोजाना एसएमएस प्राप्त होगा। यह वास्तविक समय की जवाबदेही और क्लासरूम में सीखने के लिए निरंतर



सकारात्मक माहौल की ओर बढ़ रहे पंजाब का प्रतीक है। इस कार्यक्रम को पंजाब की शिक्षा क्रांति में अगली बड़ी छलांग बनाते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब, जो पहले ही परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान विश्लेषण) सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है, अब क्लासरूम जवाबदेही को मजबूत करके और जांचे-परखे शिक्षा

अभ्यासों को अपनाकर रचनात्मक नतीजों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिक्षा बजट बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंड फाइलों में अटके रहने की बजाय क्लासरूम तक पहुंचें। इससे सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर नतीजों तक सार्थक बदलाव आएगा।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब के शीर्ष स्थान का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मिशन समर्थ 2026-27 के हिस्से के रूप में उपस्थिति ट्रेकिंग सिस्टम की शुरुआत की है।